दैनिक
नईदुनिया
भोपाल एवं सागर से एकसाथ प्रकाशित

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आज

वर्ष- 78 (भोपाल : वर्ष 40 अंक 99, पृष्ठ 12) | शनिवार 8 मार्च 2025 | राजधानी संस्करण | कीमतः 3:00 रुपये

गुजरात के सूरत में बोले प्रधानमंत्री...

जब कोई छूटेगा नहीं तो कोई रूठेगा कैसे, हर गरीब की गारंटी लेगा मोदी

सूरत(एजेंसी)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान का शुभारंभ किया और पात्र लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत लाभ वितरित किए।

एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस पहल के हिस्से के रूप में, प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत लगभग 2 लाख पात्र लाभार्थियों को लाभ वितरित किए। इस पहल का उद्देश्य व्यापक खाद्य सुरक्षा कवरेज सुनिश्चित करना है, जिससे वंचितों को आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता को बल मिलता है। मोदी ने इस दौरान कहा कि सूरत अनेक मामलों में गुजरात का, देश का एक लीडिंग शहर है। सूरत आज गरीब को, वचिंत को भोजन और पोषण की सुरक्षा देने में आगे निकल रहा है। यहां आज जो खाद्य सुरक्षा, परिपूर्णता अभियान चलाया गया है, ये दूसरे जिलों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। ये परिपूर्णता अभियान सुनिश्चित करता है- न कोई भेदभाव, न कोई छूटे, न कोई रूठे और न कोई किसी को ठगे। ये तुष्टिकरण की भावना को छोड़कर संतुष्टिकरण की पवित्र भावना को आगे बढ़ाता है। जब सरकार ही लाभार्थी के दरवाजे पर जा रही है, तो कोई छूटेगा कैसे और जब कोई छूटेगा नहीं तो कोई रूठेगा कैसे। जब सोच ये हो कि हमें सब तक लाभ पहुंचाना है, तो ठगने वाले दूर भाग जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत की यात्रा में पौष्टिक भोजन की बड़ी भूमिका है। हमारा लक्ष्य देश के हर परिवार को पर्याप्त पोषण देने का है ताकि कुपोषण और एनीमिया जैसी बड़ी समस्याओं से देश मुक्त हो सके। उन्होंने कहा कि आज, दुनिया भर के कुछ सबसे बड़े संगठन इस बात को स्वीकार करते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान ने गांवों में बीमारियों को कम करने में मदद की है। हर घर जल अभियान, जो स्वच्छ पानी तक पहुंच सुनिश्चित करता है, ने भी बीमारियों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि पहले एक जगह का राशन कार्ड दूसरी जगह नहीं चलता था।

हमने इस समस्या का समाधान किया। हमने वन नेशन वन राशन कार्ड लागू किया। अब राशन कार्ड चाहे कहीं का भी हो, लाभार्थी को उसका फायदा देश के हर शहर में मिलता है। मोदी ने कहा कि बीते दशक में पूरे देश में हमने गरीब को सशक्त करने के लिए मिशन मोड पर काम किया। गरीब के इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच बनाया गया ताकि उसे किसी के सामने भी हाथ फैलाने की नौबत न आए। पक्का घर हो, शौचालय हो, गैस कनेक्शन हो, नल कनेक्शन हो... इससे गरीबों को नया आत्मविश्वास मिला। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीमा का एक सुरक्षा कवच गरीब परिवार को दिया गया। पहली बार करीब 60 करोड़ भारतीयों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया। इसके अलावा हमारी सरकार ने गरीब को, निम्न मध्यम वर्ग को बीमा का सुरक्षा कवच भी दिया। आज देश में 36 करोड़ से ज्यादा लोग सरकारी बीमा योजनाओं से जुड़े हैं और अब तक 16,000 करोड़ रुपये से ज्यादा क्लेम राशि के रूप में इन परिवारों को दिया जा चुका है।

नमामि गंगे कार्यक्रम का कार्यकाल एक साल बढ़ा

सरकार ने अपनी महत्वकांक्षी योजना नमामि गंगे कार्यक्रम-एनजीपी को एक साल आगे खिसकाते हुए अगले वर्ष मार्च तक बढ़ा दिया है। जल शक्ति मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए शुक्रवार को बताया कि सरकार ने गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए जून 2014 में 'नमामि गंगे कार्यक्रम' एक एकीकृत संरक्षण मिशन की शुरुआत की थी। सरकार ने 20,000 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ इसे 'महत्वाकांक्षी कार्यक्रम' के रूप में अनुमोदित किया था और इसका उद्देश्य गंगा के प्रदूषण में प्रभावी कमी लाना और इसका संरक्षण करना था। राष्ट्रीय गंगा योजना को 2025-26 के लिए 3400 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय आवंटित किया गया है औ इस निवेश का मसकद सीवेज उपचार क्षमता को बढ़ाना, गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता में सुधार करना और इसके संरक्षण के साथ ही 2025 तक निर्धारित स्नान मानकों को प्राप्त करने के लिए औद्योगिक कचरे के निर्वहन को विनियमित करना है।

गरीबों और वंचितों को ध्यान में रखकर नीति और कार्यक्रम लागू करें अधिकारीः मुर्मु

नईदिल्ली(एजेंसी)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने अधिकारियों से गरीबों और वंचितों को ध्यान में रखकर नीति और कार्यक्रम लागू करने को कहा है। श्रीमती मुर्मु ने शुक्रवार को यहां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 126वें इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लेने वाले राज्य सिविल सेवा अधिकारियों से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की।

राष्ट्रपति ने इस अवसर पर अधिकारियों से प्रशासनिक कामकाज , सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में एक राष्ट्रीय और समावेशी दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी। श्रीमती मुर्मु ने कहा कि शासन का सार लोगों की जरूरतों के प्रति जवाबदेही और संवेदनशीलता में निहित है। नागरिक-केंद्रित प्रशासन लोगों के कल्याण को प्राथमिकता देता है, गरीबों और वंचितों पर ध्यान केंद्रित करता है। उन्होंने उन्हें यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि नीतियों और कार्यक्रमों को इस तरह से लागू किया जाए, जो उनकी चिंताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करे। उन्होंने कहा कि वे जो निर्णय लेते हैं और जो नीतियां लागू करते हैं, वे देश और लोगों के विकास में योगदान दें। राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण क्षरण की चुनौतियों से निपटने के लिए पर्यावरण अनुकूल पहलों को बढ़ावा देना आवश्यक है। साथ ही, विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से वंचितों और हाशिए पर पड़े लोगों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से अपने कामकाज में स्थिरता और समावेशिता के सिद्धांतों को बनाए रखने का आग्रह किया।

राहुल ने गुजरात में की पार्टी नेताओं के साथ बैठक

नईदिल्ली(एजेंसी)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज गुजरात के अहमदाबाद में पार्टी के प्रदेश, जिला तथा ब्लॉक स्तर के नेताओं के साथ बैठक कर जमीनी स्तर पर पार्टी की स्थिति का जायजा लिया।

श्री गांधी के साथ इस बैठक में संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल, कांग्रेस के गुजरात के प्रभारी महासचिव मुकुल वासनिक, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शक्तिसिंह गोहिल, विधानसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित चवदा आदि व कांग्रेस नेता मौजूद रहे। कांग्रेस नेता के गुजरात के कार्यक्रम में आज सबसे पहले कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति के नेताओं के साथ राजीव गांधी भवन में मुलाकात के बाद जिला कांग्रेस अध्यक्षों से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने ब्लॉक लेवल के नेताओं के साथ भी बैठक की।

खास-खबर

वायुसेना का जगुआर लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त

पंचकूला(एजेंसी)। भारतीय वायुसेना (आईएएफ) का जगुआर लड़ाकू विमान शुक्रवार को सिस्टम में खराबी के कारण हरियाणा के पंचकूला के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट विमान को आबादी वाले इलाकों से दूर ले जाने में सफल रहा और फिर सुरक्षित बाहर निकल गया। विमान ने प्रशिक्षण उड़ान के लिए अंबाला एयरबेस से उड़ान भरी थी। एक वीडियो में विमान का मलबा जमीन पर बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कुछ हिस्सों में अभी भी आग लगी हुई है। भारतीय वायुसेना के अनुसार, पायलट को सिस्टम में खराबी का सामना करना पड़ा और सुरक्षित रूप से बाहर निकलने से पहले उसने विमान को आवास से दूर ले गया।

शाह सीआईएसएफ स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल

चेन्नई(एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को तमिलनाडु के रानीपेट जिले के थक्कोलम में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के 56वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। सीआईएसएफ क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आरटीसी) में गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त करने और रस्मी परेड देखने के बाद श्री शाह ने सीआईएसएफ कर्मियों का साहसिक अभ्यास देखा। इस अभ्यास में आतंकवादी ताकतों को बेअसर करना, आतंकवादी हमलों के प्रयासों को विफल करना, आतंकवादियों से बंधकों को छुड़ाना, खोजी कुत्तों और अन्य मॉक ड्रिल का उपयोग करके बमों का पता लगाना तथा उनका निपटान करना शामिल था। इससे पहले, श्री शाह ने आरटीसी पहुंचने के साथ ही इसका नाम बदलकर सदियों पहले युद्ध में शहीद हुए चोल राजकुमार की याद में राजादित्य चोलन क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आरटीसी) कर दिया।

महिलाओं से किया वादा पूरा करेगी भाजपा सरकार

दिल्लीवालों को आज मिलेंगी दो सौगातें

नईदिल्ली(एजेंसी)। दिल्ली सरकार शुक्रवार दोपहर को दो बड़ी कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करने वाली है, जिसमें 'महिला समृद्धि योजना' और होली और दिवाली के दौरान मुफ्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने की योजना शामिल है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, दिल्ली कैबिनेट कल सुबह 11 बजे होने वाली बैठक में दोनों योजनाओं को मंजूरी देगी। मंजूरी के बाद दोपहर 12 बजे के बाद जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में औपचारिक घोषणा की जाएगी। दिल्ली में रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 2,500 रुपये प्रति माह की महिला समृद्धि योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में पात्र महिलाओं को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सूत्रों के अनुसार, दिल्ली सरकार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे धनराशि हस्तांतरित करेगी। छत्रसाल स्टेडियम में लॉन्च कार्यक्रम के दौरान कुछ लाभार्थियों को पहली किस्त मिल सकती है।

पांच दिनों के दौरे पर बिहार पहुंचे मोहन भागवत

पटना(एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक मार्गदर्शक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र चुनावों में भगवा पार्टी की जीत में अहम भूमिका निभाई। दिल्ली में, आरएसएस ने शहर भर में 50,000 से ज़्यादा बैठकें कीं, जिससे मतदाताओं को भाजपा के पीछे एकजुट किया जा सके। दिल्ली चुनाव के नतीजों के तुरंत बाद, आरएसएस ने अपना ध्यान बिहार और पश्चिम बंगाल पर केंद्रित कर दिया। अब, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पांच दिवसीय दौरे पर राज्य में पहुंचे हैं, जिसके दौरान वे कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और अन्य कार्यक्रमों में भाग लेंगे। आरएसएस प्रमुख 9 मार्च तक मुजफ्फरपुर में रहेंगे।

स्पेशल खबर *स्टालिन ने परिसीमन का डर पंजाब और बंगाल तक बढ़ाया...*

सात मुख्यमंत्रियों को लिखा पत्र, बैठक के लिए बुलाया

चेन्नई(एजेंसी)।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुक्रवार को बंगाल की ममता बनर्जी, पंजाब के भगवंत मान और भाजपा शासित ओडिशा के मोहन चंद्र माझी सहित सात समकक्षों से केंद्र द्वारा प्रस्तावित परिसीमन अभ्यास के खिलाफ राजनीतिक दलों की संयुक्त कार्रवाई समिति में शामिल होने का आव्हान किया। उन्होंने केरल के पिनाराई विजयन, कर्नाटक के सिद्धारमैया, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू के साथ-साथ इन राज्यों में गैर-सत्तारूढ़ दलों और भाजपा के वरिष्ठ राजनेताओं को 22 मार्च को चेन्नई में एक बैठक में सामूहिक पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए कहा है। एमके स्टालिन ने एक्स पर कहा कि परिसीमन संघवाद पर एक जबरदस्त हमला है, जो संसद में हमारी जायज आवाज को छीनकर जनसंख्या नियंत्रण सुनिश्चित करने वाले राज्यों को दंडित करता है। हम इस लोकतांत्रिक अन्याय की अनुमति नहीं देंगे! पत्र में उन्होंने परिसीमन पर चर्चा के लिए आगे की दिशा में सामूहिक रूप से चर्चा करने के लिए 22 मार्च को चेन्नई में एक उद्घाटन बैठक का प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने लिखा, यह क्षण नेतृत्व और सहयोग की मांग करता है, राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर हमारे सामूहिक हित के लिए खड़ा होना चाहिए। अगले वर्ष तमिलनाडु में होने वाले चुनावों से पहले, स्टालिन और उनकी सरकार केंद्र की हिंदी थोपने और परिसीमन का जोरदार विरोध कर रही है, उनका तर्क है कि इनमें से कोई भी आवश्यक नहीं है और कुल मिलाकर यह संविधान की संघीय प्रकृति और तमिल लोगों और भाषा पर हमला है।